एमसीएफ में हो गया खेल, नए ज्वाइंट कमिश्नर की विवादास्पद नियुक्ति

पेज एक का शेष

ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान : हर चुनौती का मुकाबला

आए। सीमा ने सीधा सीएम से शिकायत की। जब भाजपा विधायक ने प्रशांत अटकान के तबादले के लिए जोर लगाया तो अटकान अदालत से स्टे आर्डर ले आए। उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर सील करने और तोड़फोड़ का अभियान चलाया। हालांकि इस दौराना कुछ मकानों-दुकानों की सील खुलने पर वो विवाद में भी आए लेकिन सीमा और अटकान आमने-सामने अड़े रहे। इस वजह से निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खेमेबंदी कर ली, कुछ सीमा के साथ हो गए तो कुछ अटकान के विश्वासपात्र बन गए। बहरहाल, प्रशांत अटकान इस समय राजनीतिक भूमाफिया और अवैध फॉर्म हाउस मालिकों की लॉबी को पूरी तरह चुभ रहे हैं। इसलिए एक सामान्य सा दिखाई देने वाला तबादला आदेश पूरा एक खेल है। हाल ही में अरावली जोन में बनाए जा रहे उज्जवल फॉर्म के खिलाफ भी अटकान ने एफआईआर कराई थी। आरोप है कि उज्जवल फॉर्म में एक केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार का भी पैसा लगा है। सूत्रों ने बताया कि एक अन्य भाजपा नेता ने अरावली जोन में कई दुकानें अवैध रूप से बनाना शुरू कीं तो अटकान पर ऊपर से दबाव डलवाकर कार्रवाई से रोक दिया गया। इसमें एक पावरफुल भाजपा सांसद के रिश्तेदार का भी नाम आया था।

फॉर्म हाउस और बाकी जमीनें बचाएगा नया अफसर

खोरी-लकड़पुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। वहां बंधुआ मुक्ति मोर्चा हजारों लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए पैरवी कर रहा है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान से मुलाकात कर उन्हें अरावली में बने अवैध फॉर्म हाउसों, आश्रमों, मंदिरों, क्रिकेट अकादमियों, शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा दिया और कहा कि गरीब उजाड़े जा रहे हैं तो ये अमीर लोग कैसे बच सकते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान ने अरावली जोन के तमाम फॉर्म हाउसों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज मालिकों, आश्रम वालों और अन्य बिल्डिंग वालों को तलब कर लिया। उन्होंने संबंधित थाने की पुलिस को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने दो-तीन फॉर्म हाउसों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अपने हाथ खींच लिए। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत अटकान से न सिर्फ कुछ नेताओं, उनके समर्थकों बल्कि कई अफसरों ने कहा कि वे फॉर्म हाउस मामले में ज्यादा पंगेबाजी न करें। प्रशांत अटकान ने इन सलाहों को दरकिनार कर अपना अभियान जारी रखा। सूत्रों के मुताबिक आला अफसरों के कान तब खड़े हुए जब कुछ फॉर्म हाउसों को लेकर उन्होंने कानूनी राय तक मांग ली। अभी जब डीसी यशपाल यादव के फरीदाबाद नगर निगम का भी चार्ज था, वो अटकान के रवैए और काम से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। इधर विधायक सीमा त्रिखा और पार्षदों की शिकायतें सीएम खट्टर के पास लगातार पहुंच रही थीं। भाजपा सूत्रों ने सीएम से यह तक कहा कि यह अधिकारी मुझे और पार्टी को फरीदाबाद में बर्बाद कर देगा।

सीमा त्रिखा का नजदीकी अफसर

समझा जाता है कि नए ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव की नियुक्ति बहुत सोच समझकर एमसीएफ में की गई है। इसे इस तरह समझें। जितेन्द्र यादव बडखल क्षेत्र के एसडीएम भी रह चुके हैं। उस दौरान वह विधायक सीमा के बहुत नजदीक थे। बडखल तहसील में सीमा का कोई भी गलत-सही काम नहीं रुकता था। जब उनका तबादला होने लगा तो सीमा ने जितेन्द्र यादव को फरीदाबाद में ही रखने का आग्रह सीएम से किया। इसके बाद उन्हें हूडा में संपदा अधिकारी लगाया गया और अब सीमा की ही सलाह पर एमसीएफ में नया पद बनाकर उन्हें यहां भी लाया गया। सीमा ने सीएम खट्टर को सलाह दी थी कि ज्वाइंट कमिश्नर बडखल के नाम से अलग पद बनाया जाए लेकिन हरियाणा नगर निगम एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है तो उस प्रस्ताव की जगह यह हल निकाला गया। प्रशांत अटकान से छुटकारा पाने के लिए यह पूरा खेल रचा गया। इसीलिए जितेन्द्र यादव के पद को अस्थायी भी रखा गया है। प्रशांत अटकान का स्टे जब कभी हटेगा तब अस्थायी वाला पद भी खत्म हो जाएगा।

लॉकडाउन के नाम पर मचाई पुलिस ने लूट,असली जिम्मेदार हैं उच्चाधिकारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सड़कों पर मास्क व पास का धंधा इन दिनों पुलिस की लूट कमाई का एक बढिया साधन साबित हो रहा था। 'हूडा' सेक्टर की एक मार्केट में तो पूलिस ने हर दुकान से चार-चार हज़ार तक की उगाही केवल इसी बात की कर ली कि वे उन्हें समय की पाबंदी से मुक्त रखेंगे। दो-तीन सैलून वालों ने साफ़ इन्कार करते हुए कह दिया कि वे तो सरकार द्वारा निर्धारित समयानुसार ही चलेंगे तो उन्हें 'देख लेने' तक ही धमकी दे डाली।

इसी तरह, एक 15 सेक्टर निवासी ने खाली बैठे किसी मज़दूर-मिस्त्री को अपने फ़ार्म हाउस पर ट्यूबवैल का काम करने भेजा तो तत्काल पुलिस पहुच गयी, जो पुलिस किसी वारदात पर पहुंचने में घंटों लगा देती है, इस ट्यूबवैल स्थल पर मिन्टों में पहुंच गयी। मजे की बात यह रही कि मज़दूर-मिस्त्री को डराने-धमकाने के बाद थाने ले जाने की अपेक्षा कह दिया कि खेत मालिक को फ़ोन करे कि वह 30 हज़ार लेकर थाने पहुंच जाये। लेकिन मालिक भी पूरा खेला-खाया घैंट निकला, उसने मज़दूर से कह दिया कि वह चिंता न करे, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो करले, जमानत करा लेंगे। बेचारे पुलिस वाले अपना सा मुंह लेकर रह गये।

उक्त दो किस्से तो उदाहरण मात्र हैं, वरना सारे ज़िले में यही सब कुछ हो रहा है। यह असंभव है कि इतने चौड़े में खुले आम मची यह लूट ज़िले भर में बैठे तमाम उच्चाधिकारियों को दिखाई न देती हो। दरअसल छोटे पुलिसकर्मियों की सुपरविज़न करने वाले उच्चाधिकारियों की मर्जी एवं आशीर्वाद के बिना किसी छोटे कर्मी की हिम्मत नहीं कि वह इस तरह लूट मचा सके। असल बात तो यह है कि छोटे कर्मी तो बदनाम ज्यादा होते हैं मोटा माल तो पर्दे के पिछे बैठे उच्चाधिकारी, केवल अपनी आंखें बंद रखने के बदले, मारते हैं। जनता ने अपने जिन प्रतिनिधियों को चुन कर अफ़सरशाही की लगाम कसने के लिये भेज रखा है, वे खुद भी इसी लूट में साझेदार होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला...

पेज एक का शेष

आश्रम क्यों बचाए जा रहे हैं। इनके मालिकों ने जिनसे जमीन खरीदी थी क्या वे लोग अरावली की इस जमीन के वास्वविक मालिक थे। हरियाणा सरकार ने किस आधार पर सिद्धदाता आश्रम, राधा स्वामी सत्संग को यहां पर जमीन आवंटित कर दी। क्या झुग्गी-झोंपड़ी या मकान बनाकर रह रहे गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए अलग कानून है और फ़ॉर्म हाउस मालिकों और मोटी फीस लेने वाले शिक्षण संस्थाओं के लिए अलग कानून है। मजदूर मोर्चा ने इससे पहले भी इस मामले को लगातार उठाया है।

सबसे बड़ी भूमाफिया हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पीएलपीए) में बदलाव कर फरीदाबाद-गुड़गांव में अरावली की जमीनों को लुटा दिया। इनमें वन विभाग की जमीन शामिल है। करीब 60,000 एकड़ अरावली की जमीन प्रॉपर्टी डीलरों और खनन माफिया को सौंप दी गई। अभी भी अरावली में करीब 50,000 एकड़ ऐसी जमीन है जिसे कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार इस जमीन को वन क्षेत्र का दर्जा देने को तैयार नहीं है। अगर 50,000 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो यह जमीन भी बच सकती है। मांगर इलाके में जंगल की जमीन पूरी तौर पर वन क्षेत्र है लेकिन हरियाणा सरकार इसे वन क्षेत्र घोषित नहीं कर रही है। फरीदाबाद-गुड़गांव के पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार मांग करते रहे हैं कि मांगर में 677 एकड़ और बफर जोन की 1200 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार फाइल पर कुंडली मारकर बैठी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद इस इलाके में पहुंचे थे, तब भी यह मांग रखी गई थी। उन्होंने वादा भी किया था लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

इसकी वजह है राजनीतिक। अरावली में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। वन क्षेत्र घोषित होते ही अवैध खनन की दुकानें बंद हो जाएंगी। खनन मंत्री और माइनिंग डिपार्टमेंट इस अवैध धंधे को चैनलाइज करने के लिए ही बनाए गए हैं। किसी भी दल की सरकार हो, सभी राजनीतिक दलों के नेता, सांसद, विधायक और मंत्री इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं। करतार भड़ाना, अवतार भड़ाना ने अरावली का दोहन कर अरबों की समपत्ति बनाई। जब इनका सितारा डूबा तो अब दूसरे गूजर नेताओं ने इनकी जगह ले ली। पिछले दिनों मजदूर मोर्चा में ही एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक केन्द्रीय मंत्री के संरक्षण में यहां उज्जवल फॉर्म हाउस का बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में एफआईआर भी हुई लेकिन मामला वहीं का वहीं रहा। उससे आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बडखल रोड पर पेट्रोल पंप के सामने बाकायदा अवैध दुकानों का निर्माण किया गया। यह भी अरावली का इलाका है। एमसीएफ ने यहां एक बार तो दुकानों की दीवार गिरा दी। लेकिन करनाल के भाजपा सांसद का आदमी बताकर कथित तौर पर फोन किया गया और एमसीएफ ने कार्रवाई रोक दी। इसके बाद फरीदाबाद भाजपा के नेताओं ने अरावली जोन में इन अवैध दुकानों को बनवा दिया। इसके पीछे की सरकारी जमीन पर भी कब्जा हो चुका है। हूडा और एमसीएफ को अरावली क्षेत्र की अपनी जमीनों की चिन्ता ही नहीं है।

गुड़गांव के सिटी पार्क को भी खतरा

भूमाफिया सिर्फ फरीदाबाद में ही नहीं गुड़गांव की बेशकीमती जमीनों पर भी नजर गड़ाए हुए है। गुड़गांव में अरावली बॉयोडायवर्सिटी पार्क की देखरेख गुड़गांव नगर निगम कर रहा है। लेकिन अभी मौजूदा हालात ये हैं कि यहां पर कंटीले तारों की बाड़ को नष्ट कर दिया गया है। यहां पर हाल ही में कुछ पौधे भी लगे थे, वे भी नष्ट हो गए हैं। दरअसल, भूमाफिया इसी तरह जमीनों पर कब्जा करता है। कुछ दिनों में यहां किसी धार्मिक स्थल का निशान बना दिया जाएगा। फिर कुछ लोग वहां हुक्का गुड़गुड़ाने के लिए बैठने लगेंगे। फिर वे उस जमीन को अपने बाप-दादा की जमीन बताकर बेच देंगे। अरावली बॉयोडायवर्सिटी पार्क गुड़गांव शहर के लिए फेफड़े का काम करता है। इसका असर फरीदाबाद तक के पर्यावरण पर पड़ता है। लेकिन हरियाणा सरकार को इस बेशकीमती जमीन को बचाने की फिक्र नहीं है। इस जमीन पर पहले से ही काफी कब्जा है।

कुछ चुभने वाले अवैध निर्माण

फरीदाबाद और गुड़गांव के अरावली जोन में कुछ चुभने वाले अवैध निर्माण हैं। सिद्धदाता आश्रम, राधास्वामी सत्संग के अलावा जगतगुरु धाम और करीब 50 गौशाला वनक्षेत्र की जमीनों पर बनाई गई हैं। गौशाला सिर्फ नाम की हैं, वहां और भी व्यावसायिक कार्य होते हैं जिनसे गौशाला की आड़ लेने वालों को आमदनी होती है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि गौशालाओं को हम हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि इन्हें सीधे हरियाणा सरकार का संरक्षण प्राप्त हैं। इसके अलावा गौरक्षा दल वाले भी जरा सी कार्रवाई होने पर उत्पात मचाने लगते हैं।

इसी तरह यहां करीब 25 प्राइवेट क्रिकेट अकादमी या क्रिकेट गुरुकुल और जिम खुले हुए हैं। ज्यादातर क्रिकेट अकादमी फॉर्म हाउसों में हैं। क्रिकेट क्लबों के बीच मैच कराए जाते हैं और उन पर सट्टा तक लगाया जाता है। मानव रचना यूनिवर्सिटी, अरावली इंटरनैशनल स्कूल और कई अन्य संस्थाओं के बारे में मजदूर मोर्चा पहले ही लिख चुका है।

इन चुभते हुए अवैध निर्माणों के बीच हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ खोरी और लकड़पुर में हजारों मजदूर परिवारों के घर ही नजर आए। हैरानी की बात है कि इस बस्ती के लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमने भाजपा को वोट दिया था लेकिन अब ये लोग हैरान हैं कि इतना बड़ा धोखा उन्हें कैसे मिल गया? इस संबंध में बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में यहां के लोगों का पुनर्वास किए जाने को लेकर एक याचिका भी लगाई है लेकिन अदालत ने उस याचिका को अभी स्वीकार नहीं किया है।

बिजली - पानी बंद, 15 से एक्शन

खोरी और लकड़पुर की अवैध बस्ती में प्रशासन के आदेश पर फिलहाल बिजली-पानी बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने बस्ती वालों को स्पष्ट कह दिया है कि 15 जून से वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। बेहतर है कि लोग उससे पहले ही अपना सामान वगैरह वहां से हटा लें और कब्जा खाली कर दें। खोरी में बिजली सप्लाई कुछ ठेकेदारों के जरिए मिल रही थी। ये ठेकेदार सरकारी सप्लाई को अपनी लाइनों के जरिए खोरी और लकड़पुर की बस्ती में पहुंचा रहे थे, इसके बदले ठेकेदार बस्ती वालों से 15 रुपये प्रति यूनिट वसूलते थे। बिजली विभाग की नाक के नीचे यह गैरकानूनी काम हो रहा था और विभाग को इसकी भनक तक नहीं थी। इसी तरह यहां पानी के लिए मोटी पाइपलाइनें बिछी हुई हैं। पानी सप्लाई की पाइप लाइनें कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से मशहूर हैं। जिन पाइपलाइनों को कांग्रेसी नेताओं और पार्षदों ने बिछवाया वो कांग्रेसी कहलाती हैं, उसी तरह जिन पाइपलाइनों को भाजपाइयों ने बिछवाया वो भाजपाई कहलाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एमसीएफ ने वहां मुनादी कराई और नोटिस चिपकाये। हालांकि पहले यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई 9 जून से ही शुरू करने की बात कही गई लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न मिलने के कारण कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी।

पुलिस वालों ने बेची जमीनें, अब लगा रहे आरोप

खोरी में पुलिस की नूरा कुश्ती जारी है। खोरी में जब पिछली बार तोड़फोड़ हुई थी तो वहां रहने वालों ने आरोप लगाए थे कि कुछ पुलिस वाले हमारी बस्ती से वसूली करके ले जाते थे। कुछ पुलिस वालों ने हमें जमीन तक बेची। हम लोग पुलिस संरक्षण मिलने से खुश थे कि हमें अब कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ। तमाम लोगों ने कैमरे के सामने बयान दिए हैं कि उन्हें पुलिस वालों ने जमीन दिलवाई या जमीन बेची। लेकिन अब पुलिस ने गोदी मीडिया के एक समाचारपत्र में खबर प्लांट कराई है कि इस बस्ती में अपराधी आकर छिपते हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था तो उसने रोका क्यों नहीं? क्या पुलिस ने कभी सर्वे किया कि यहां कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। पुलिस यह आंकड़ा भी नहीं दे सकी कि उसने यहां से कितनी संख्या में ऐसे बदमाशों को पकड़ा जो यहां शरण लिए हुए थे। एकाध को पकड़ लेने से उसे पूरी बस्ती के लिए सामान्य नहीं कहा जा सकता। कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से लगे दाग को उसके अधिकारी गोदी मीडिया में खबरें प्लांट कर अपनी छवि बचाना चाहते हैं।

सहयोग के लिये सुधी पाठकों का धन्यवाद

'मज़दूर मोर्चा' की अपील का संज्ञान लेते हुए सुधी पाठकों ने जो आर्थिक सहयोग दिया एवं भविष्य में देते रहने का संकल्प किया है, उससे 'मज़दूर मोर्चा' आर्थिक संकट से काफ़ी हद तक उबर पाया है। दरअसल, बिक्री के दम पर चलने वाले इस साप्ताहिक पर कोरोना की मार काफ़ी भारी पड़ गयी। मार्च 2020 वाले लॉकडाउन तक जहां 4000 हजार प्रतियां बिकती थी, डेढ़ माह बंद रहने के बाद 400 प्रतियों से शुरू करके 1700 तक पहुंच पाये थे कि फ़िर लॉकडाउन ने वापस 1000 पर ला पटका। लेकिन अब धीरे-धीरे वापस बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं इन दिनों न्यूज प्रिंट की कीमत भी 30 प्रतिशत बढ़ गयी।

लेकिन सुधी पाठकों ने जिस तरह से सहयोग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है वह काबिले तारीफ़ तो है ही अनापेक्षित भी लगा। फ़रीदाबाद से बाहर के तो अनेक ऐसे पाठकों ने सहयोग दिया जिनको हम निजी तौर पर जानते-पहचानते भी नहीं। स्थानीय ग़रीब मज़दूर पाठकों ने खुद मिल कर 50-50 रुपये का योगदान देते हुए जिस लहजे में कहा कि मेहनतकश वर्ग की इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे, हमें भावुक कर दिया। इससे यह भरोसा पक्का हो गया है कि उद्योगपतियों व राजनेताओं की गोदी में बैठे बगैर, पाठकों के सहयोग से भी कोई अखबार चलाया जा सकता है।

सम्पादक मंडल

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad